

# चौका सकते हैं भाजपा प्रत्याशियों के नाम

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल

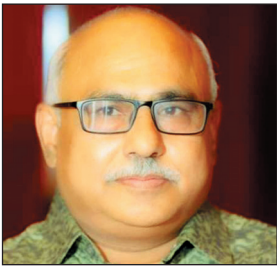
► **जार्ज कुरियन को रिपोर्ट करने के पक्ष में नहीं भाजपा संगठन**

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 28 मई. प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त हो रही तीन सीटों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रदेश के दावेदारों की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात का महत्व बढ़ गया है।

समझा जा रहा है कि इस मुलाकात में खंडेलवाल ने राज्यसभा और राष्ट्रीय

कार्यकारिणी में प्रदेश की भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की। इस बार राज्यसभा के लिए दौ चौकाए वाले नाम सामने आए हैं, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रदेश के कद्दावर मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

दरअसल राज्यसभा के लिए इस बार भाजपा प्रदेश के ही नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में है। यानी जार्ज कुरियन को रिपोर्ट किए जाने के पक्ष में नहीं है, वहां जा रहा है कि इस संबंध में प्रदेश के भाजपा पदाधिकारियों की भावना से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवागत करा दिया गया है। दरअसल कुरियन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें



केरलम में पराजय का सामना करना पड़ा। यानी संदेश साफ है कि राष्ट्रीय संगठन भी कुरियन को प्रदेश की राजनीति में वापस भेजना चाह रही है।

वहीं विधानसभा चुनाव हारने से कुरियन का ग्राफ भी गिर गया है। ऐसे में उन्हें मप्र से राज्यसभा चुनाव के लिए फिर उम्मीदवार बनाएगी इसकी संभावना कम दिख रही है। बताया जा रहा है कि

दावेदारों में अरविंद भदौरिया और रामपाल सिंह भी

बताया जा रहा है कि भदौरिया के लिए संघ लॉबी जबरदस्त पैरवी कर रहा है। इधर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी जून में होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के नेताओं की भागीदारी भी तय है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, वहीं उन्हें ऐसे राज्य का प्रदेश प्रभारी बनाया जा सकता है, जहां निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का नाम भी उभरा है। रामपाल सिंह को केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान का करीबी माना जाता है।

इसकी भरपाई एक और बाहरी नेता अरविंद मेनन से की जा सकती है। मेनन भी मूल रूप से केरल से ही आते हैं।

वहीं अरविंद मेनन प्रदेश में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनकी प्रदेश के नेताओं के साथ बेहतर बाइंडिंग भी है। यदि बाहरी के नाम पर अरविंद मेनन को मप्र से उम्मीदवार बनाया गया तो

प्रदेश भाजपा खुले मन से उनका साथ दे सकती है, लेकिन यदि किसी और बाहरी को उम्मीदवार बनाया गया तो फिर उन्हें खुले मन से स्वीकार करना आसान नहीं होगा। हालांकि खुले तौर पर विरोध करना प्रदेश के नेताओं के लिए आसान भी नहीं होगा। वहीं राज्यसभा को दूसरी सीट के लिए अरविंद भदौरिया का नाम भी प्रमुखता से उभरा है।

दीवार ढहने से मलबे में दबकर मजदूर की मृत्यु

मुरैना, 28 मई. जिले के कैलारस थाना क्षेत्र में आज पानी की टंकी की दीवार ढहने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसा ग्राम राजपुरा स्थित एक ईट भट्टे पर हुआ। उत्तरप्रदेश के महोबा निवासी मजदूर ब्रजेंद्र प्रजापति (25) सुबह पानी की टंकी के नीचे बैठकर नहा रहा था। इसी दौरान टंकी की दीवार अचानक बरभराकर गिर गई। जिसके बाद वह मलबे में दब गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि ईट भट्टा मालिक के खिलाफ टंकी निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

शिक्षा व्यवस्था माफिया और बिचौलियों के हवाले

विशेष संवाददाता  
भोपाल, 28 मई. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देशभर में सामने आ रहे परीक्षा घोटालों, पेपर लीक, भर्ती अनियमितताओं और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह माफियाओं, बिचौलियों और भ्रष्ट कंपनियों के हवाले कर दिया गया है, जिससे लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के सपने टूट रहे हैं।

जीतू पटवारी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2018 से लगातार सामने आ रहे



पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने युवाओं के भविष्य की रक्षा करने वाली संस्थाओं की विफलता

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम का ठेका कोम्पट नामक कंपनी को दिया गया, जो पहले तेलंगाना में रलोबेनाना नाम से विवादों में रह चुकी है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से खवाल किया कि उक्त कंपनी को ठेका देने की अनुमति किसने दी, क्या निविदा प्रक्रिया में नियमों को दरकिनारा किया गया और पहले से विवादों में रहने के बावजूद कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई। पटवारी ने मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाले को राजनीतिक संरक्षण में चल रहे 'शिक्षा माफिया' का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।

उजागर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल टैरिस्टिंग एजेंसी (एनटीए) अब विश्वसनीय परीक्षा संस्था के बजाय विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का प्रतीक बन गई है। उन्होंने सीबीएसई परीक्षा परिणामों में कथित विसंगतियों पर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि रिजल्ट में गड़बड़ियों के कारण कई विद्यार्थी और अभिभावक परेशान हैं तथा कॉलेज प्रवेश की पात्रता प्रभावित हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम का ठेका कोम्पट नामक कंपनी को दिया गया, जो पहले तेलंगाना में रलोबेनाना नाम से विवादों में रह चुकी है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से खवाल किया कि उक्त कंपनी को ठेका देने की अनुमति किसने दी, क्या निविदा प्रक्रिया में नियमों को दरकिनारा किया गया और पहले से विवादों में रहने के बावजूद कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई। पटवारी ने मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाले को राजनीतिक संरक्षण में चल रहे 'शिक्षा माफिया' का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।

नौतपा में दोहरी मार : कहीं लू, कहीं बारिश का अलर्ट

46 जिलों में भीषण गर्मी का असर जारी है

46 डिग्री सेल्सियस खजुराहो और नौगांव

भोपाल, 28 मई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश में नौतपा के बीच मौसम ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर राज्य के 46 जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं।

गैरजरूरी प्रवासों पर नकेल

अंक मिलान के लिए महालेखाकार कार्यालय में दल भेजने पर जताई आपत्ति

► **वित्त विभाग ने दूसरे विभागों के अफसरों को चेताया**

कन्हैया लोधी  
भोपाल, 28 मई. ऐसे समय जब राज्य सरकार खर्च नियंत्रित करने के लिए बचत के मोड में आ गई है, तब अफसरों के गैरजरूरी प्रवास पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। हाल ही में वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजा है, जिसमें उन्हें विभागों के हिसाब का ब्यौरा देने के लिए ग्वालियर स्थित महालेखाकार कार्यालय में जाने के चलन को गैर जरूरी बता दिया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि वहां विभागों के खर्च के अंक मिलान के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उस पूरे वित्तीय वर्ष

की अवधि में राज्य के अलग-अलग विभागों में कितना और कैसे खर्च किया है, इसका पूरा ब्यौरा महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को देना होता है। इसे अंक मिलान की प्रक्रिया भी कहा जाता है। वैसे अंक मिलान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वित्त विभाग ने वर्ष 2020 से ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की है। यानी विभाग ऑनलाइन तरीके से भी अंक मिलान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन

वित्त विभाग की इस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि में किए गए खर्च का ब्यौरा देने के लिए अपने स्तर पर ही विभागीय अफसरों का दल लगातार ग्वालियर महालेखाकार कार्यालय भेज रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे समय जब राज्य सरकार बचत के मोड में है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी लगातार बचत का संदेश दे रहे हैं।

► **सरकार खजाने पर वित्तीय भार घटाने की तैयारी**

सीएम कॉरिडोर में वाहनों की संख्या में कटौती कर दी है। कई बार वे सार्वजनिक परिवहन वाहनों में यात्रा कर रहे हैं। इसी तरह मंत्री भी इसी राह पर चल निकले हैं और डीजल, पेट्रोल बचाने के साथ ही खर्च को नियंत्रित करने का संदेश दे रहे हैं। तब अनाश्यक रूप से अफसरों के प्रवास से इसका भार तो सरकारी खजाने पर ही आता है, लिहाजा वित्त विभाग ने सभी विभागों को संवत किया है कि वे अंक मिलान के नाम पर अफसरों के ग्वालियर प्रवास को रोकें।

7 दिन में बरामद हुए सड़क पर गिरे 6 लाख रुपये

विशेष संवाददाता  
भोपाल, 28 मई. मुरैना जिले की अम्बाह थाना पुलिस ने तत्परता और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए सड़क पर गुप्त हुए छह लाख रुपये बरामद कर फरियादी को सुरक्षित लौटा दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से आमजन में भरोसा और मजबूत हुआ है।

पुलिस के अनुसार, चंबल कॉलोनी निवासी योगेश सिंह तोमर ने 19 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से सेंट्रल बैंक में छह लाख रुपये जमा करने जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास रुपयों से भरे बैग की चेन खुल गई,



मुरैना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मोना के निर्देशन में अम्बाह थाना प्रभारी वीरेश सिंह कुशवाह के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की पहचान कर सात दिन के भीतर पूरी राशि बरामद कर ली।

जिससे नोटों के बंडल सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रहे एक बाइक

अवैध क्लीनिक और स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई जारी

उज्जैन, 28 मई. जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक, अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध सघन जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में गठित विशेष जांच दल द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 140 स्थानों पर जांच की गई है। इनमें 28 अर्पजीकृत पाए गए, अर्पजीकृत संस्थानों में से 18 को सील किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार

पटेल ने बताया कि विभाग द्वारा गठित जांच दल ने 10 मई से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया है। क्लीनिकों के पंजीयन के लिए अब तक 57 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें होम्योपैथिक के 25, आयुर्वेदिक के 16, एलोपैथी के 11, डेंटल के तीन और पैथालॉजी के दो आवेदन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यकतानुसार संबंधित संस्थानों को बंद कराने, दस्तावेजों की जांच, पंजीयन सत्यापन और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

जीआरपी ने 8 घंटे में मासूम को किया बरामद

विशेष संवाददाता  
भोपाल, 28 मई. जीआरपी भोपाल ने त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच के दम पर रेलवे स्टेशन से अपहृत दो वर्षीय बालक को महज आठ घंटे के भीतर सफल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। रेल पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया। कार्रवाई का नेतृत्व जीआरपी भोपाल थाना प्रभारी निरीक्षक जहीर खान ने किया। टीम ने



तकनीकी और मैदानी जांच के जरिए आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार कटनी निवासी सीतू यादव 26 मई को अपने पति के साथ मजदूरी की तलाश में भोपाल आई थीं। उनका पति काम की तलाश में चला गया, जबकि वह अपने दो वर्षीय पुत्र के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन के

प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 स्थित मुसाफिरखाने के पास बैठे थीं। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बच्चे को खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया।

शिकायत मिलते ही जीआरपी ने रेलवे स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को लेकर इटारसी दिशा की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार होता दिखाई दिया। तकनीकी विश्लेषण और निगरानी के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और ट्रेन क्रमांक 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच से उतरते समय उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया।



काश्यप ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से किया संवाद

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 28 मई. एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया।

काश्यप ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका।

गेहूं खरीदी का आंकड़ा अब 104.22 लाख मीट्रिक टन पहुंचा

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 28 मई. प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ है। मप्र को गेहूं खरीदी के लिये 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था। राज्य सरकार के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने इस लक्ष्य को 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। शुक्रवार खरीदी का आखिरी दिन है।

मप्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13 लाख 41 हजार 266 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नम्बर-1 है, वहीं गेहूं उपार्जन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे

आज उपार्जन का आखिरी दिन



स्थान पर है। कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों से सबसे पहले गेहूं की खरीदी की गई। कुल 8 लाख 9 हजार 990 सीमांत एवं लघु कृषकों से 32 लाख 14 हजार

संभावित कहां कितना उपार्जन

रीवा संभाग में 6 लाख 15 हजार 851 मीट्रिक टन, जबलपुर में 12 लाख 73 हजार 667, शहडोल में 70 हजार 666, सागर में 8 लाख 56 हजार 968, भोपाल में 28 लाख 47 हजार 284, नर्मदापुरम में 9 लाख 22 हजार 508, उज्जैन में 22 लाख 84 हजार 47, इंदौर में 8 लाख 62 हजार 719, ग्वालियर में 4 लाख 36 हजार 805 और चंबल संभाग में 2 लाख 40 हजार 581 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है।

मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में हो रहे गेहूं उपार्जन की सतत मॉनिटरिंग की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर तौल व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और

खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये उपलब्ध जरूरी सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। साथ ही किसानों से संवाद कर उपार्जित गेहूं के भुगतान आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लाट बुक करा लिये थे, उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी थी।



साहू समाज का दो दिवसीय सम्मेलन महिला सशक्तिकरण पर जोर

जबलपुर, 28 मई. कचनार सिटी में मध्यप्रदेश तैलिक साहू सभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया।

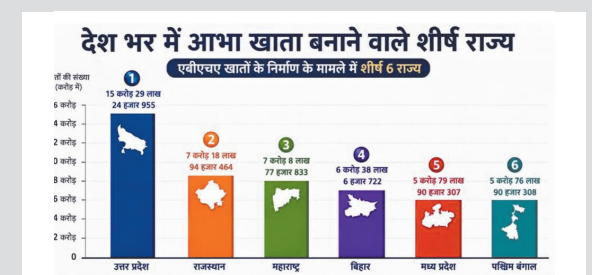
देशभर से समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, जगप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदत्त छौरसागर ने कहा कि जो सामाजिक संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, वे देश में अपनी अलग पहचान बनाते हैं।

डिजिटल रिकॉर्ड देश भर में 100 करोड़ से अधिक लोगों के दर्ज हुए हेल्थ रिकॉर्ड

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मप्र देश में 5 वें स्थान पर

साक्षी केसरवानी  
भोपाल, 28 मई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मुताबिक देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 100 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित कर लिया है।

वहीं अगर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों यानी आभा खाते (एबीएचए अकाउंट) की बात करें, तो देश में अब तक कुल 89 करोड़ 76 लाख 46 हजार 673 खाते बन चुके हैं। बता दें आभा खाता एक तरह का स्वास्थ्य खाता है, जिसके तहत व्यक्ति के इलाज



को हिस्ट्री डिजिटल रूप से सुरक्षित रखी जाती है। वहीं मप्र ने ऐसा करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में अपनी जगह पक्की कर ली है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोगों ने बनाए आभा खाते: देश भर के राज्यों में उत्तर प्रदेश 15 करोड़ 29 लाख 24 हजार 955 आभा खातों के साथ

पहले पायदान पर है। वहीं मप्र 5 करोड़ 79 लाख 90 हजार 307 खातों के साथ 5 वें स्थान पर है। जबकि राजस्थान 7 करोड़ 18 लाख 94 हजार 464 खातों के साथ दूसरे, महाराष्ट्र 7 करोड़ 8 लाख 77 हजार 833 खातों के साथ तीसरे, बिहार 6 करोड़ 38 लाख 6 हजार 722 आभा खातों के साथ

प्रदेश में इंदौर जिला अक्वल

प्रदेश में इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 25.2 लाख आभा खाते बन चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल 18.2 लाख खातों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो छिंदवाड़ा और सागर भी 18.2 लाख खातों के साथ बराबरी पर चल रहे हैं। इसके बाद धार में 17.4 लाख, रीवा में 17 लाख, और जबलपुर में 16.5 लाख स्वास्थ्य खाते बन चुके हैं।

आभा खाते और रिकॉर्ड लिंक से क्या है लाभ

आभा खाता और उससे रिकॉर्ड लिंक होने से मरीजों को घरे और जांच रिपोर्ट का भारी-भरकम पुलिदा साथ लेकर चलने के झंझट से मुक्ति मिल सकेगी। इससे देश के किसी भी अस्पताल में डॉक्टर मरीज की पूर्ण सहमति से उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से देखकर तुरंत सटीक इलाज शुरू कर सकते हैं।

आगे रहे पुरुष : एनएचए के अनुसार आभा खाता बनाने में मप्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भागीदारी थोड़ी अधिक रही है। कुल खातों में से 50.32 प्रतिशत

प्रदेश में एक माह में 4 लाख से अधिक नए खाते बने

अगर पिछले एक महीने यानी 26 अप्रैल से 26 मई 2026 तक की प्रगति देखें, तो मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान 4 लाख 20 हजार 171 नए आभा खाते बनाए गए हैं। जबकि बंगाल में इस एक महीने के भीतर कई राज्यों से अधिक 68 लाख 50 हजार 501 नए खाते तैयार किए गए हैं। जो यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर लोग डिजिटल हेल्थ आईडी के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं।

खाते पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 49.68 प्रतिशत दर्ज की गई है। वहीं अन्य वर्ग की भागीदारी अभी शून्य प्रतिशत के आसपास है।